

रक्षा अध्ययन एवं विश्लेषण संस्थान

रक्षा अध्ययन एवं विश्लेषण संस्थान (आईडीएसए) एक निष्पक्ष, स्वायत्त तथा पंजीकृत सोसाइटी है, जो रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वित्तपोषित है। इस संस्थान की स्थापना 11 नवम्बर, 1965 को नई दिल्ली में हुई। आईडीएसए का उद्देश्य रक्षा और सुरक्षा के सभी पहलुओं का विस्तृत और नीतिगत अध्ययन करना है। विगत वर्षों के दौरान, यह संस्थान सामरिक मामलों पर देश का सर्वप्रमुख नीति विचारक संगठन (थिंक टैंक) बन कर उभरा है।

आईडीएसए को दिनांक 11 नवम्बर, 1965 को सोसाइटी के रूप में पंजीकृत किया गया। राष्ट्रीय सुरक्षा को समर्पित एक निष्पक्ष और स्वायत्त शोध संस्थान स्थापित करने की पहल तत्कालीन रक्षा मंत्री श्री यशवंतराव चव्हाण ने की, जो इस संस्थान के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। 1962 के भारत-चीन युद्ध के बाद एक ऐसे शोध संस्थान की स्थापना की आवश्यकता महसूस की जाने लगी, जोकि सरकार का अंग होते हुए सुरक्षा के समग्र वातावरण के बारे में नीति-निर्धारकों की जानकारी बढ़ाने के साथ-साथ सरकार द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली वैकल्पिक नीतियों का भी सुझाव दे।

आईडीएसए के स्थापन के अनुसार, इस संगठन का उद्देश्य "राष्ट्रीय सुरक्षा की समस्याओं के साथ-साथ रक्षा संबंधी उपायों का आर्थिक, सामाजिक तथा राजनैतिक प्रतिक्रिया पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन, इन पर विचार-विमर्श और शोध करना" तथा "रक्षा अध्ययन एवं विश्लेषण, सामरिक नीति, निरस्त्रीकरण और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से जुड़े विषयों पर शोध तथा सूचना के आदान-प्रदान को प्रोत्साहित करना है।" विगत वर्षों के दौरान, आईडीएसए के शोध और विश्लेषण के दायरे का विस्तार हुआ है। समय की जरूरत को समझते हुए, सुरक्षा के पारम्परिक विषयों के साथ-साथ संस्थान ने सुरक्षा के गैर-पारम्परिक पहलुओं को भी अपने शोध का महत्वपूर्ण क्षेत्र बनाया है।

वर्ष 2007 में इस संस्थान द्वारा घोषित इसकी संकल्पना में इसका कार्यकलापों को अधिक स्पष्ट रूप से व्यक्त किया गया है और इसमें नीतिपरक शोध, प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण और लोक शिक्षा पर अधिक जोर दिया गया है। इस संस्थान ने भारत की विदेश तथा सुरक्षा संबंधी नीतियों के निर्धारण में अहम भूमिका निभाई है। परमाणु शक्ति, सैन्य व्यय तथा भारत के समग्र उत्पन्न पारम्परिक तथा गैर-पारम्परिक खतरों से संबंधित क्षेत्रों में इस संस्थान का योगदान विशेष रूप से उल्लेखनीय है।

आईडीएसए का वृहत उद्देश्य, कूटनीतिक क्षेत्र से जुड़े भारत तथा विश्वभर के विशाल समुदाय के सदस्यों को, रक्षा तथा सुरक्षा संबंधी नई जानकारीयाँ और ज्ञान प्रदान कर राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ावा देना है। इस संस्थान ने राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े विभिन्न विषयों पर संवाद स्थापित करने के मंच की भूमिका भी निभाई है। यह संस्थान गोष्ठियों, सम्मेलनों, मोल मेज सम्मेलनों और कार्यशालाओं का नियमित रूप से आयोजन करता रहता है। इनमें कूटनीतिक क्षेत्र में कार्यरत लोगों के अतिरिक्त अकादमिक जगत के विशेषज्ञ, पत्रकार तथा सामरिक क्षेत्र के विश्लेषक आदि शामिल होते हैं। इस प्रकार, यह संस्थान नए विचार विकसित करने, उनके विश्लेषण तथा देश के शीर्षस्थ निर्णायकों द्वारा इन विचारों को प्रयोग में लाए जाने के दृष्टिकोण से इनके नीतिगत पहलुओं का बायीं से अध्ययन करने में मदद करता है।

आईडीएसए पूर्णतः रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वित्तपोषित है। इसका प्रशासन कार्य एक तटस्थ और निष्पक्ष कार्यकारी परिषद द्वारा संचालित किया जाता

है। इस परिषद में गणमान्य व्यक्तियों का शामिल किया जाता है, जोकि आम समा द्वारा दो वर्ष की अवधि के लिए निर्वाचित किए जाते हैं। उस परिषद का प्रमुख एक अध्यक्ष होता है, जिसकी सहायता के लिए विभिन्न समितियों का गठन किया जाता है। ये समितियाँ संस्थान के विविध कार्यों का संचालन करती हैं। इस संस्थान के भागीदार पक्षों में सरकार के साथ-साथ संसद, कूटनीतिक समुदाय, मीडिया और जनसामान्य के सदस्य भी शामिल हैं।

हालांकि, आईडीएसए, रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वित्तपोषित है, परन्तु इसने सदा अपनी स्वायत्तता को बनाए रखा है। इस संस्थान की संरचना ही इसकी स्वायत्तता बनाए रखने में सहायक सिद्ध होती है। इस संस्थान की कार्यकारी परिषद में इसके अध्यक्ष तथा निर्वाचित सदस्यों के साथ-साथ सरकार के कुछेक पूर्व-पदेन सदस्य भी शामिल होते हैं। यह परिषद कार्मिक, स्थापना, प्रशासन आदि से संबंधित सभी मामलों में निर्णय करने के लिए पूर्णतः अधिकृत है। शोध का एजेंडा, संस्थान के निदेशक द्वारा निर्धारित किया जाता है। यह प्रवृत्ति पूर्णतः कारगर रही है तथा सरकार द्वारा वित्तपोषित अन्य संस्थानों के लिए इस मामले में मिसाल पेश करती है कि किस प्रकार संस्थानों की स्वायत्तता को बनाए रखा जाए।

इस संस्थान के शोधकर्ताओं में विभिन्न विद्यालयों के अत्यंत सुयोग्य व अनुभवी व्यक्तियों को शामिल किया जाता है। विविधता के दृष्टिकोण से इनका ध्यान अकादमिक क्षेत्र के साथ-साथ रक्षा सेवकों तथा सिविल सेवकों में से किया जाता है। इस विविधता के कारण पारस्परिक विषयों को समझने और उन्हें विकसित करने के साथ-साथ संस्थान में होने वाले शोध कार्य की गुणवत्ता को सुदृढ़ बनाने में भी मदद मिलती है। शोधकर्ताओं का ध्यान सज्जात्कार के माध्यम से किया जाता है। समर्पित शोधकर्ताओं के अतिरिक्त यह संस्थान सेवारत सरकारी कर्मियों, सैन्य कर्मियों, अकादमिक क्षेत्र तथा मीडिया जगत के सदस्यों को समय-समय पर अपने शोधकर्ता तथा शिक्षक मंडल में शामिल होने हेतु प्रोत्साहित करता रहता है।

संस्थान के शोध संबंधी कार्यकलापों का संचालन इसके विभिन्न केंद्रों द्वारा किया जाता है। ये केंद्र विविध क्षेत्रों पर फोकस करते हैं।

एक नई शक्ति के रूप में उभरते भारत की प्रतिष्ठा के साथ-साथ राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आईडीएसए का महत्व भी काफी बढ़ा है। इस पृष्ठभूमि में आईडीएसए ने अपनी भूमिका बखूबी निभाई है और नीति-निर्धारकों से संवाद स्थापित करने के साथ-साथ कूटनीतिक विषयों के बारे में जनसामान्य की जागरूकता बढ़ाने की दिशा में अहम भूमिका अदा की है। आईडीएसए के प्रकाशनों की तटस्थता और इनकी गुणवत्ता ने यह सुनिश्चित किया है कि नीति विचारक संगठन के रूप में इस संस्थान की प्रतिष्ठा देश के साथ-साथ विदेशों में भी सर्वमान्य है।

डाक विभाग, रक्षा अध्ययन एवं विश्लेषण संस्थान पर एक स्मारक डाक-टिकट जारी करते हुए प्रसन्नता का अनुभव करता है।

आभार :-

मूलपाठ : प्रस्तावक द्वारा उपलब्ध कराई गई सामग्री पर आधारित
डाक-टिकट/प्रथम दिवस : नीनू गुप्ता
आवरण/विरूपण



तकनीकी आंकड़े TECHNICAL DATA

मूल्यवर्ग Denomination	:	500 पैसा 500 p
मुद्रित डाक-टिकटें Stamps Printed	:	6.0 लाख 0.6 Million
मुद्रण प्रक्रिया Printing Process	:	वेट ऑफसेट Wet Offset
मुद्रक Printer	:	प्रतिभूति मुद्रणालय, हैदराबाद Security Printing Press Hyderabad

© डाक विभाग, भारत सरकार। डाक-टिकट, प्रथम दिवस आवरण सूचना विवरणिका के संबंध में सर्वाधिकार विभाग के पास है।

© Department of Posts, Government of India. All rights respect to the stamp, first day cover and information brochure with the Department.

INSTITUTE FOR DEFENCE STUDIES AND ANALYSES

The Institute for Defence Studies and Analyses (IDSA) is a non-partisan, autonomous, registered, society, funded by the Ministry of Defence, Government of India. Established in New Delhi on November 11, 1965, the IDSA is dedicated to objective and policy relevant studies on all aspects of defence and security. Over the years, it has emerged as the nation's premier think tank on strategic affairs.

The IDSA was registered as a society on November 11, 1965. The initiative for setting up a non-partisan, autonomous research institute dedicated to national security came from then Defence Minister Shri Yeshwantrao Chavan, who was one of the Institute's founding members. In the aftermath of the 1962 Sino-Indian war, a need was felt to establish a research outfit aligned to the government, both to educate policy makers about the larger security environment and to provide policy alternatives for use by the government.

As per IDSA's memorandum, the objective of the organization was "to initiate study, discussion and research on problems of National Security and impact of Defence measures on economic, social and political processes", and to promote research and exchange of information on "defence studies and analyses, strategy, disarmament and international relations". Over the years, the ambit of research and analysis of IDSA has expanded. In tune with the times, along with traditional hard security issues, the institution has added non-traditional security issues as an important area of research.

The vision statement of the institute adopted in 2007 brings further clarity to its activities and emphasizes on policy-oriented research, training and capacity building and public education. The Institute has played a crucial role in shaping India's foreign and security policies. Its contribution has been particularly visible in areas related to nuclear weapons, military expenditure, and conventional and non-conventional threats to India.

The IDSA's larger mission has been to promote national and international security through generation and dissemination of knowledge on defence and security issues among the larger strategic community in India and the world. It has also served as a forum to debate various issues related to national and international security. Through regular seminars, conferences, roundtables, and workshops, attended by practitioners, academics, journalists and strategic analysts, the Institute helps generate ideas, analyses and policy inputs relevant for use by the decision makers of the country.

The IDSA is funded entirely by the Ministry of Defence, Government of India. It is governed by a neutral and non-partisan Executive Council, comprising distinguished personalities, elected for a period of two years, by the general body. The Council is headed by a president and supported by committees covering different aspects of the Institute's work. The stakeholders include Government, Parliament, Strategic Community, Media and the General Public.

Although the IDSA is funded by the Ministry of Defence, Government of India, it has all through protected and maintained its autonomy. The structure of the Institute helps it to maintain its autonomy. The Executive Council of the Institute, which consists of elected members including the President and a few ex-officio members from the government, is fully empowered to take decisions pertaining to personnel, establishment, administration etc. The Director of the Institute decides the research agenda. The system has functioned well and is a model for other government funded institutes as to how best to maintain their autonomy.

The institute has a well-qualified multi-disciplinary research faculty drawn from academia, defence forces and the civil services, representing a diversity of views. This helps in cross-fertilization of ideas and strengthens the quality of research. The faculty is chosen through open interviews. Apart from a dedicated research faculty, the Institute encourages serving officials from government, military services, academics and media to join as faculty from time to time.

The research activities of the Institute are conducted by different centres focusing on different areas.

India's growing profile as an emerging power has helped the IDSA raise its profile nationally and internationally. Against this setting, the IDSA has positioned itself well, and played a key role in interacting with policymakers and raising awareness about strategic issues in the public. The objectivity of IDSA publications as well as their quality has ensured that the institute is seen as a respectable think tank in the country and abroad.

Department of Posts is pleased to release a Commemorative postage stamp on Institute for Defence Studies and Analyses.

Credits:-

- Text : Based on the material received from proponent
- Stamp/FDC : Nenu Gupta
- Cancellation

भारतीय डाक विभाग
DEPARTMENT OF POSTS
INDIA



रक्षा अध्ययन एवं विश्लेषण संस्थान
INSTITUTE FOR DEFENCE STUDIES AND ANALYSES

विवरणिका BROCHURE